इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 08 मार्च 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
अर्थव्यवस्था---------- 3
पण्य (जिंस) बाज़ार ---------- 4
सहकारी बैंक ---------- 4
बीमा ---------- 4
सूक्ष्म वित्त ---------- 5
उत्पाद एवं गंठजोड़ ----------5
विनियामक के कथन ---------- 5
विशिष्ट घटनाएं ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ---------- 7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 26 फरवरी, 2010 को 2010-11 के लिए केन्द्रीय बजट घोषित किया। बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रासंगिक उक्त बजट की कुछेक मुख्य बातें निम्नानुसार थीं :

- भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों की भौगोलिक व्याप्ति को विस्तारित करने और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की संस्थाओं और गैर-वित्तीय बैंकिंग कम्पनियों को कुछेक अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान किए जाने पर विचार कर रहा है।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक पूंजी प्राप्त होगी, ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित उधार को समर्थन देने हेतु पर्याप्त पूंजी आधार मौजूद हो।

- 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा इन गांवों को बीमा और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराना। ये सेवाएं कारबार संपर्की मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदान की जाएंगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग सेवाएं बैंकिंग-सुविधा रहित क्षेत्रों तक पहुंचें, वित्तीय समावेशन निधि तथा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि, प्रत्येक में 100 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

बचत खातों पर ब्याज कम करने हेतु बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से स्वीकृति मांगी

वाणिज्यिक बैंक चाहते हैं कि आगामी दैनिक ब्याज भुगतान प्रणाली में उनके निवल ब्याज मार्जिन को संरक्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक बचत बैंक (SB) जमाराशियों पर ब्याज दर को 3.5 % से घटा कर 2.5 - 3.0 % करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करे। वर्तमान में बचत बैंक खातों पर ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह के 10वें और अंतिम दिन के बीच वाली अवधि में रखे गए जमा-शेषों पर की जाती है। इसलिए, प्रभावी तौर पर वेतनभोगी खाता धारक माह के पहले नौ दिनों के लिए कोई ब्याज नहीं अर्जित

करते। जैसे-जैसे माह बीतता जाता है वेतन-अर्जक के खाते में जमाशेष घटता जाता है तथा वह केवल न्यूनतम जमा शेष पर ही ब्याज अर्जित कर पाता / पाती है। प्रभावी रूप से बैंकों के लिए ब्याजगत परिव्यय 3.5 % से काफी कम होता है, क्योंकि वे पर्याप्त निर्बंध अस्थायी निधियों का उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक बैंक 1 अप्रैल, 2010 से बचत बैंक खातों पर दैनिक आधार पर ब्याज भुगतान प्रणाली लागू हो जाने पर अपने निवल ब्याज मार्जिन को संरक्षित रखना चाहते हैं।

आईडीबीआई बैंक ने परिवर्तनशील वेतन लागू किया

आईडीबीआई बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए परिवर्तनशील वेतन अपना लिया है, जो अब 70 % का स्थिर वेतन संघटक प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया में वह इस ढांचे में अंतरित होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है, क्योंकि अन्य बैंकों ने कर्मचारी संघों (यूनियनों) के विरोध के कारण इस योजना को त्याग दिया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मानव संसाधन नीतियों के पुनरीक्षण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ. ए.के. खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है - जिसमें विचार-विमर्श किए जाने वाले मुद्दों में परिवर्तनशील वेतन एक प्रमुख मुद्दा होगा। बैंक ने वेतनों में लगभग 20 % की बढ़ोत्तरी भी की है।

बैंक कृषि लक्ष्यों को आधारभूत सुविधा ऋणों से असम्बद्ध किए जाने के इच्छुक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ साख नीति के पश्चात् वाली हाल ही की एक बैठक में बैंकरों ने आधारभूत सुविधा परियोजनाओं को वृद्धिशील ऋण प्रवाह की एक शर्त के रूप में कृषि उधार हेतु निधियां अलग रखने से छूट दिए जाने की मांग की है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले समायोजित निवल बैंक ऋणों के 40 % में से लगभग आधे अंश का उपयोग कृषि ऋणों के लिए किया जाना होता है। इसके प्रत्युत्तर में श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि समूहन, कॉरपोरेट बॉण्डों और प्रतिभूतिकरण जैसी पद्धतियों द्वारा एक्सपोजर का उल्लंघन किए बिना वैसा करना संभव है।

20 बैंक शीर्ष 500 वाली वैश्विक सूची में

भारतीय बैंक विश्व के बैंकर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बड़े वैश्विक बैंकों के लिए मंदी वाले आवरण के बीच लचीले भारतीय बैंकों ने अपना ब्रॉण्ड मूल्य तेजी से बढ़ा लिया है। इस वर्ष ब्रॉण्ड फाइनैन्स @ग्लोबल बैंकिंग 500, यू.के. स्थित ब्रॉण्ड फाइनैन्स प्लेक द्वारा की जाने वाली वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 20 भारतीय बैंकों का समावेश है; जबकि भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 50 शीर्ष बैंकों वाली सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय बैंक हो गया है।

बैंकों को नये अशोध्य ऋण मानदंडों से राहत

प्रावधान व्याप्ति अनुपात (PCR) की गणना के लिए तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले जाने वाली रकम को शामिल किए जाने से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय बैंकों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अब तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई रकम को सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा। प्रारंभ में, सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों को 70 % की अनिवार्य प्रावधान व्याप्ति अपेक्षा को पूरा करने के लिए जनवरी और सितम्बर की अवधि के बीच 12,105 करोड़ रुपये अलग रखे जाने की आवश्यकता हो सकती थी। किन्तु मार्च, 2009 तक तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई रकमों को जोड़ दिए जाने पर इस अपेक्षा में 9,630 करोड़ रुपये की कमी हो गई है और अब यह कमी लगभग 2,475 करोड़ रुपये रह जाएगी।

कॉरपोरेशन बैंक को पुरस्कार

कॉरपोरेशन बैंक ने अपनी कारबार से सम्बन्धित पहलकदमियों में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां लागू करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA), फिनैकल एण्ड ट्रेड फेयर्स एण्ड कॉन्फरेंस इंटरनेशनल (TFCI) के तत्वावधान में आयोजित बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2009 में पुरस्कार हासिल किया है। बैंक को यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 2009 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 'बेस्ट ऑनलाइन एण्ड मल्टी-चैनेल बैंकिंग इनिशियेटिव कटेगरी' में प्रदान किया गया है।

सरकार ने बैंकों के विलयन और अभिग्रहण की योजना ठंडे बस्ते में डाली

सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्त किए गए प्रतिकूल विचारों, राजनीतिक क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित रूखेपन तथा बैंक यूनियनों के विरोध के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच विलयन एवं अभिग्रहण (M&As) पर चर्चा करना रोक दिया है। दिसम्बर, 2009 में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों, यथा - पंजाब नैशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) से बैंकिंग उद्योग में विलयन के अवसरों का पता लगाने के लिए कहा था। हालांकि, अब यह विचार जैसे ताक पर रख दिया गया हो।

भारतीय बैंकिंग ब्रिक (BRIC) प्रतिस्थानियों के मुकाबले मज़बूत : फिक्की सर्वेक्षण

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (FICCI) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का कहना है कि भारतीय बैंकिंग महत्त्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों पर ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है; इसने अपने लचीलेपन को बनाए रखा है तथा वह विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। भारतीय विनियामक प्रणाली चीन, ब्राजील और यू.के. से श्रेष्ठ है। जोखिम प्रबन्धन प्रणाली चीन, ब्राजील और रूस की प्रणालियों से उत्कृष्ट है तथा ऋण की गुणवत्ता चीन, ब्राजील, रूस, यू.के और संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर है। भारत की बैंकिंग प्रौद्योगिकी प्रणालियां भी ब्राजील और रूस की तुलना में श्रेष्ठ हैं। भारतीय बैंकिंग उद्योग की विनियामक प्रणाली तथा विदेशी बाज़ार से आनुपातिक पृथक्करण ने इसे वर्तमान अस्थिर आर्थिक वातावरण में लचीली बनाए रखा है।

ऑनलाइन निधि अंतरण को और समय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) का परिचालन समय सप्ताह के दिनों दो घंटे और शनिवार को एक घंटा बढ़ा दिए जाने के परिणामस्वरूप 1 मार्च से ग्राहकों को ऑनलाइन निधि अंतरण करने के लिए और समय प्राप्त होगा। अब राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) सुविधा सप्ताह के दिन प्रात: 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध होगी। शनिवार को यह प्रात: 9.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने घण्टेवार निपटान की संकल्पना लागू की है। इससे सप्ताह के दिनों में दैनिक निपटान पूर्ववर्ती छ: से बढ़ कर ग्यारह हो जाएंगे। भारत में लगभग 63,000 बैंक शाखाएं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) की अंग हैं।

बैंक बिक्री केन्द्रों से एक दिन में 1,000 रुपये के आहरण की अनुमति देंगे

ग्राहकों को बिक्री केन्द्र (PoS) आउटलेटों से प्रति दिन 1,000 रुपये तक के आहरण की अनुमति दे कर बैंक अब अपने चालू खातों, बचत खातों (CASA) के अंश, जो सावधि जमाराशियों की तुलना में सस्ते होते हैं, को बढ़ाने की आशा करते हैं। इस योजना को उनके लिए बैंक-रहित क्षेत्रों तक पहुंच बना कर वित्तीय समावेशन बढ़ाने में भी सहायक होना चाहिए। वर्तमान में भारत में चार लाख बिक्री केन्द्र टर्मिनल मौजूद हैं; अगले पांच वर्षों में इस संख्या में तीन गुणा वृद्धि होने की संभावना है। बिक्री केन्द्रों की वृद्धि एटीएमों अथवा डेबिट कार्डों, जो लगभग 40 % प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं, को पीछे छोड़ सकती है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के कई एक बैंकों के पास बहुत सारे बिक्री केन्द्र आउटलेट नहीं हैं। भारतीय स्टेट बैंक आगामी पांच वर्षों में 6 लाख से अधिक बिक्री केन्द्र प्राप्त करने की योजना बना रहा है। इसी प्रकार, बैंक ऑफ इंडिया एक वर्ष के भीतर 1 लाख बिक्री केन्द्र प्राप्त करने की योजना बना रहा है।

टीजर दर पर ऋण लेने वालों का अभाव

गृह ऋणों के मामले में बैंकों के टीजर दर प्रस्ताव नये उधारकर्ताओं को आकर्षित करने में विफल हो गए हैं। इन योजनाओं में पहले कुछेक वर्षों के लिए कम नियत ब्याज दर तथा उसके बाद अस्थिर दर की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों से यह पता चलता है कि आवासीय ऋणों का प्रवाह नवम्बर, 2008 से नवम्बर, 2009 तक 7.3 % अथवा 19,820 करोड़ रुपये बढ़ा। इसके प्रतिकूल, गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि 10.4 % रही। मार्च के अंत से दिसम्बर, 2009 के अंत के बीच वाली अवधि में बैंकों के गृह ऋण संविभाग और आवासीय ऋण कम्पनियों के ऋण 8.7 % बढ़ कर 4,13,700 करोड़ रुपये हो गए। उसी अवधि में बैंक ऋण 8.8 % बढ़ा।

डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु बैंकों ने अन्य पक्ष का विकल्प अपनाया

मुद्रा लेनदेन लागत को कम करने के लिए नकदी लेनदेनों को हतोत्साहित करने के अपने प्रयासों में बैंकों ने ग्राहकों को अतिरिक्त लाभों के साथ डेबिट कार्डों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के नवोन्मेषी तरीके खोज निकाले हैं। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक निष्ठा एवं पुरस्कार प्रबन्धन कम्पनी लॉयल्टी रिवार्ड्स के साथ तीन वर्ष की गंठजोड़ व्यवस्था की है। वर्तमान में इस गंठजोड़ में भारतीय स्टेट बैंक के मुंबई के 6.7 करोड़ डेबिट कार्ड प्रयोक्ताओं का समावेश है। हालांकि, बैंक इस सुविधा को अपने सम्पूर्ण ग्राहक आधार तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। श्री अमिताभ कुमार, महा प्रबन्धक (वैकल्पिक चैनल), भारतीय स्टेट बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि "इस गंठजोड़ व्यवस्था के पश्चात् हमारे डेबिट कार्डों के उपयोग में उल्लेखनीय बढोत्तरी हुई है।"

बचत खातों पर दैनिक आधार पर ब्याज अप्रैल से

वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण के संतोषजनक स्तर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान 1 अप्रैल, 2010 से दैनिक गुणनफल के आधार पर किया जाएगा। बचत जमाराशियों के मामले में ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह के 10वें दिन से ले कर अंतिम दिन की अवधि के दौरान जमा खाते में न्यूनतम जमा शेष पर की जाएगी तथा उसे खाते में केवल तभी जमा किया जाएगा, जब वह 1 रुपया या उससे अधिक हो।

पुराने निजी बैंकों ने जमा दरें बढ़ाना शुरू किया

ब्याज दरों में वृद्धि का संकेत करते हुए (एचडीएफसी बैंक से शुरूआत होते हुए) कई एक निजी बैंकों ने इस बात को स्वीकार करने के बावजूद कि प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि मौजूद है, अपनी जमा दरों को बढ़ाना आरंभ कर दिया है। यह वृद्धि कुछेक समय-समूहों में ही की गई है, न कि सभी स्तरों पर। इस बार का दर संशोधन उद्योग के अग्रणियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से हट कर है।

नौकरी अभियान के बाजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 22,000 रिक्तियां

बैंकों द्वारा पिछले एक वर्ष में लगभग 15,000 लोगों को नियुक्त किए जाने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 22,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। पंजाब नैशनल बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, (OBC), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक इस समय स्टाफ की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत का बैंकिंग क्षेत्र बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अंश-निष्कासन करने हेतु बैंक-रहित क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार की पृष्ठभूमि में तेजी से विकास कर रहा है। भारत में मौजूद 63,000 गांवों में से केवल 30, 000 गांवों को वाणिज्यिक बैंकों की सेवाएं प्राप्त हैं।

अर्थव्यवस्था

भारत मुद्रास्फीति के मोर्चे पर शिथिल नहीं रह सकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा, "भारत मुद्रास्फीति से संघर्ष करने में शिथिल नहीं रह सकता; हमारे लिए मूल्य-वृद्धि को 5 % या उससे कम स्तर पर नियंत्रित रखना आवश्यक है।" भारतीय रिज़र्व बैंक ने वार्षिक मौद्रिक नीति की अपनी हाल की समीक्षा में बढ़ती कीमतों से बैंकिंग प्रणाली में आने वाली अतिरिक्त मुद्रा को रोकने के लिए वह रकम बढ़ा दी थी, जो उधारदाताओं द्वारा आरक्षित निधियों (आरक्षित नकदी निधि अनुपात) के रूप में अलग रखी जानी अपेक्षित है । डॉ. चक्रवर्ती ने आगे यह भी कहा, "हम मौद्रिक प्रेरणा की व्यवस्था से लगभग बाहर निकल आए हैं; हमें आशा है कि इससे मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर रोक लगेगी।" ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार एशिया-प्रशांत देशों के बीच भारत में मुद्रास्फीति सर्वाधिक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2010 के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ा कर 6.9 % किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्प से ले कर मध्यम अवधि तक की आर्थिक घटनाओं के महत्वपूर्ण स्थूल-आर्थिक संकेतकों से सम्बन्धित व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के तिमाही सर्वेक्षण के परिणाम जारी कर दिए हैं। पूर्वानुमानकर्ताओं ने अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से सम्बन्धित पूर्वानुमानों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करते हुए उसे वर्ष 2009-10 में 6 % के स्थान पर 6.9 % कर दिया है। उनसे उस संभावना की संभाव्यता का निर्देश करने के लिए कहा गया था जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष विविध श्रेणियों में कम होगी। 43.8 % की सर्वाधिक संभाव्यता वर्ष 2009-10 की 6.5 - 6.9 % की वृद्धि श्रेणी के लिए निर्देशित की गई है। वर्ष 2010-11 के लिए उन्होंने 33.8 % की सर्वाधिक संभाव्यता सकल घरेलू उत्पाद की 8 - 8.4 % की वृद्धि श्रेणी के लिए निर्देशित की है। उक्त सर्वेक्षण में भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों या पूर्वानुमानों का किसी भी रूप में प्रतिबिंबन नहीं होता।

खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित मुद्रास्फीति बढ़ कर 17.97 % हुई

खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित वार्षिक मुद्रास्फीति ने (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 17.94 % की तुलना में) 6 फरवरी को 17.97 % बढ़ कर फरवरी के प्रारंभ में पुन: सिर उठा लिया है। कई एक खाद्य उत्पादों में मुद्रास्फीति का स्तर निरंतर ऊंचा रहा, जिनमें आलू (पिछले वर्ष के स्तर से 57.67 % अधिक), प्याज (29.92 % अधिक) अग्रणी रहे। प्राथमिक वस्तुओं, जिनमें खाद्य और कच्ची खाद्येतर मदें शामिल हैं, से सम्बन्धित मुद्रास्फीति बढ़ कर 16.23 % हो गई।

बैंकों के वित्तीय परिणामों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि के प्रभावों को सुलभ चलनिधि नियंत्रित रखेगी

अरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में वृद्धि आम तौर पर अपेक्षाकृत अधिक बॉण्ड प्रतिफल, कमतर खज़ाना अभिलाभ तथा बैंकों के पास निधि की कम उपलब्धता का संकेत देती है, जिससे उनकी उधार देने की क्षमता प्रतिबंधित हो जाती है। हालांकि, आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 75 आधार अंकों की वृद्धि, जो बैंकिंग प्रणाली से 36,000 करोड़ रुपये अवरुद्ध करेगी, के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेहमैन की विफलता के बाद नीतिगत दरों में कटौतियों और ऋण व्यवस्था (credit lines) उपलब्ध करने के माध्यम से बैंकों मे 4 लाख करोड़ की निधि लगाए जाने के कारण प्रणाली में प्रचुर चलनिधि मौजूद है। इस प्रकार, उधार देने के लिए निधियों की कमी नहीं है; इसके विपरीत, ऋण-उठाव (जिसमें अब तक गिरावट की प्रवृत्ति मौजूद थी) में तेजी आनी शुरू हो गई है। अक्तूबर 2009 के अंत तक ऋण वृद्धि वर्षानुवर्ष 9.5 % के निम्नतर स्तर पर स्थिर थी, किन्तु इसके बाद 15 जनवरी, 2010 को बढ़ कर वर्षानुवर्ष 13.9 % के स्तर पर पहुंच गई। इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है।

जिंस बाज़ार

एमसीएक्स विश्व का छठा सबसे बड़ा जिंस बाज़ार हुआ

सोने-चांदी (बुलियन), मूल धातुओं और ऊर्जा पर संकेन्द्रण के साथ देश का सबसे बड़ा सराफा बाज़ार बहु-जिंस बाज़ार (Multi-Commodity Exchange) जनवरी-दिसम्बर 2009 की अवधि में संविदाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में जिंस क्रय-विक्रय हेतु भावी सौदों का 6ठा सबसे बड़ा बाज़ार बन गया है। एम सी एक्स ने वर्ष 2009 में 161.117 मिलियन संविदाओं का क्रय-विक्रय किया, जो वर्ष 2008 के 94.31 मिलियन से 71 % अधिक है। इस सफलता के लिए उत्तरदायी प्रमुख जिंस खण्ड सोना-चांदी, मूल धातु और ऊर्जा हैं, जिन्होंने एमसीएक्स के परिमाण में 95 % से अधिक का अंशदान किया।

एमसीडीएक्स ने बादाम के भावी सौदों की शुरूआत की

बहु-जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार (MCDEX) ने बादाम के क्रय-विक्रय हेतु भावी सौदों की शुरूआत कर दी है। भाव-पत्र (quotation) एक किलोग्राम के लिए तथा क्रय-विक्रय इकाई 900 कि.ग्रा. की होगी। सुपुर्दगी केन्द्र दिल्ली और मुंबई में हैं। बादाम का घरेलू उत्पादन 1,200 टन के स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें अधिकांश उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में होता है। देश लगभग 1,600 करोड़ रुपये के कुल बाज़ार आकार के साथ बादाम का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंकिंग वित्तीय समावेशन लाने में समर्थ

शहरी सहकारी बैंकों का भविष्य शहरी क्षेत्रों में बैंक-रहित लोगों तक पैठ बनाने में निहित है, यह विचार भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि

"वाणिज्यिक बैंक इस स्तर तक पैठ बनाने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उनका लोगों से उतना संपर्क नहीं होता, जितना कि शहरी सहकारी बैंकों का होता है। इन लोगों तक पहुंच बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को प्रौद्योगिकीय संवृद्धि लानी होगी।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कमजोर शहरी सहकारी बैंक अधिगृहीत करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों में समामेलन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों के न प्राप्त होने की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च, 2007 के दिन नकारात्मक निवल हैसियत वाले शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं (शाखाओं सहित) को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की सहायता से वाणिज्यिक बैंकों को हस्तांतरित करने पर विचार कर सकता है। उक्त योजना में जमाकर्ताओं को 100 % संरक्षण देना सुनिश्चत किया जाएगा तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की सहायता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) 1961 की धारा 16 (2) के तहत उपबंधित रकम तक ही सीमित होगी।

बीमा

जीवन बीमा पॉलिसिया शीघ्र ही कागज़-रहित हो सकेंगी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमा परिषद की बीमा क्षेत्र के डिजिटीकरण की योजना अनुमोदित किए जाने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के लिए पॉलिसियों का कागज़ी रिकार्ड शीघ्र ही इतिहास की चीज़ हो सकता है। सूचना भण्डारण का डिमैट या डिज़िटल आरूप बीमा कम्पनियों की वितरण लागत में उल्लेखनीय रूप से बचत करेगा। वर्तमान में दो निक्षेपागार (depositories) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (NSDL) लिमिटेड और केन्द्रीय निक्षेपागार (CDSL) सेवा (भारत) लिमिटेड खातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा डिमैट रूप में सामूहिक रूप से धारित करते हैं तथा उनका प्रबन्धन करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (NSDL) लिमिटेड एक करोड़ से अधिक डिमैट खातों का रख-रखाव करता है, जबकि 64 लाख से अधिक खातों का प्रबन्धन केन्द्रीय निक्षेपागार (CDSL) सेवा (भारत) लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

निजी जीवन बीमाकर्ता एजेन्टों को नवीकरण कमीशन देना बंद कर सकते हैं

जनश्रुति के अनुसार बीमा एजेन्ट एविवा और आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल जैसे कुछेक निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारायूनिट-सम्बद्ध उत्पादों (ULIPs) पर प्रभारों से सम्बन्धित अंतरों को पूरा करने के दबाव के अधीन चुनिंदा श्रेणी की पॉलिसियों के लिए पांच वर्ष के बाद नवीकरण कमीशन का भुगतान बंद किए जाने को ले कर क्षुब्ध हैं। पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के लिए 2.5 - 4 % का पूर्ववर्ती औसत कमीशन अब घटा कर 1 -2% कर दिया गया है। एजेन्टों को भय है कि इस अनुचित परंपरा का परिणाम अधिक पॉलिसियों के व्यपगत (lapsed) हो जाने के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि वितरकों को पॉलिसी धारकों को नवीकरण प्रीमियमों का समय पर भुगतान करने हेतु समझाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा। हालांकि, श्री संजीव बजाज, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, बजाज कैपिटल्स महसूस करते हैं कि "इससे कम्पनियों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें गारंटीकृत प्रतिफल का भुगतान केवल तभी करना होगा, जब ग्राहक पॉलिसी को उसकी पूरी अवधि तक जारी रखें ।"

निजी बीमाकर्ताओं ने जनशक्ति में 33,700 की कमी की

निजी बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष में अपने नेटवर्क का विस्तार करने और 660 शाखाएं खोलने के बावजूद अपनी जनशक्ति में 33,700 (18 %) की भारी कमी की है। दिसम्बर, 2009 में समाप्त तिमाही मे निजी बीमा उद्योग का कुल प्रत्यक्ष कार्य बल दिसम्बर, 2008 में 1,86 645 की तुलना में 1,52,874 था। इसी अवधि में बीमा बेचने वाले एजन्टों की संख्या में 2,10,550 की वृद्धि हुई, जिससे वह बढ़ कर 29,84,287 हो गई। यद्यपि उद्योग के प्रत्यक्ष कार्य बल में कमी हुई, निजी बीमाकर्ताओं के नये कारबार प्रीमियम में 25 % की वृद्धि हुई। श्री एस.बी. माथुर, सचिव, जीवन बीमा परिषद के अनुसार अपेक्षाकृत पुरानी निजी बीमा कम्पनियां अपने आकार में कमी ला रही हैं तथा शाखाओं का विलयन कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में कमी आई होगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि नयी कम्पनियां शाखाएं खोलने का क्रम जारी रखे हुए हैं (पिछले दो वर्षों में 5,000)।

सूक्ष्म वित्त

भारतीय रिज़र्व बैंक की फटकार के बाद सूक्ष्म वित्त संस्थाएं आचरण संहिता बनाने की तैयारी में

अग्रणी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के उधारकर्ताओं से किए जाने वाले व्यवहार के तौर-तरीकों में सुधार लाने का वचन दिया है तथा उधार दरों की मार्च के बाद समीक्षा करने का वादा किया है। प्रारंभ में स-धन, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का राष्ट्रीय संघ अपने सदस्यों के लिए एक अधिक कठोर आचरण संहिता लागू करेगा। जहां नयी संहिता लागू की जाने की तैयारी काफी लंबे समय से की जा रही है, वहीं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की परिचालनात्मक अनियमितताओं और अभिशासन से सम्बन्धित मुद्दों ने इस मामले पर शीघ्र निर्णय को आवश्यक बना दिया। उक्त संहिता में वसूली की जोर-जबरदस्ती वाली युक्तियों, उधार देने की सीमाओं, ऋणों की अतिव्याप्ति, उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह की जांच तथा सदस्यों के बीच

अनतिक्रमण (no-poaching) करार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अब अनैतिक प्रतिस्पर्धा से विरत रहने तथा अपने एक्सपोजर को अन्य ऋणदाताओं के विद्यमान उधारकर्ताओं तक ही सीमित रखने पर सहमत हो गई हैं।

उत्पाद एवं गंठजोड़

ऑनलाइन क्रय-विक्रय हेतु रेलिगेयर का बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता

रेलिगेयर सिक्योरिटीज और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने महा-ई ट्रेड नामक एक ऑनलाइन क्रय-विक्रय मंच की शुरूआत करने हेतु गंठजोड़ किया है। यह सुविधा बैंक के बचत खाता ग्राहकों के लिए मूल्य-योजित प्रस्ताव का अंग होगी, जो उन्हें रेलिगेयर द्वारा समर्थित एक बचत खाता, एक निक्षेपागार सहभागी (DP) खाता तथा एक इंटरनेट पर क्रय-विक्रय करने वाला खाता उपलब्ध कराएगी। इंटरनेट बैंकिंग समर्थित खातों वाले ग्राहकों को बैंक में डिमैट खाते तथा तीन अनुमोदित दलालों के पास व्यापारिक खाते खोलना आवश्यक होगा, जिसकी सुविधा बैंक की शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

लार्सन एण्ड टूब्रो को सामान्य बीमा उद्यम की स्वीकृति मिली

इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण महारथी लार्सन एण्ड टूब्रो (L&T) किसी संयुक्त उद्यम के बिना ही आगामी 3-4 माह में सामान्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु पूर्णत: तत्पर है। लार्सन एण्ड टूब्रो को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का आर1 अर्थात् लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु प्रारंभिक अनुमोदन, जिसमें विनियामक द्वारा प्रवर्तकों का मूल्यांकन किया जाता है, प्राप्त हो गया है। दूसरे चरण (आर2) में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कम्पनी के कारबार मॉडल की जांच करता है तथा आर3 में वह कम्पनी के गठन की जांच करता है। वर्तमान समय में देश में सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों सहित 22 सामान्य बीमा कम्पनियां परिचालनरत हैं।

येस बैंक की मोबाइल सेवा

येस बैंक ने नोकिया और ओबोपे के सहयोग से मोबाइल बैंकिंग सेवा की शुरूआत की है। इस पूर्व-प्रदत्त मोबाइल भुगतान सेवा से बैंकिंग सेवा-रहित और अल्प बैंकिंग सेवा सहित ग्राहक खंडों में वित्तीय समावेशन के बढ़ने की आशा की जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक, टीवीएस द्वारा करार हस्ताक्षरित

टीवीएस मोटर कम्पनी ने अपने व्यापारियों को आकर्षक ब्याज दरों पर स्टॉक (Inventory) निधीयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक

टीवीएस मोटर कम्पनी के 600 से अधिक व्यापारियों को उनकी कार्यशील पूंजी बढ़ाने, वाहन स्टॉक को बढ़ाने और फलत: खुदरा बिक्री बढ़ाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा। यह कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक की 'सप्लाई चेन फाइनैन्सियल यूनिट' द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा इसे एक इलेक्ट्रॉनिक मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इसकी विशेषताओं में ऑनलाइन निधि अंतरण, ऑनलाइन चुकौती तथा खाते की स्थिति का तत्काल पर्यवेक्षण शामिल हैं।

विनियामकों के कथन

सेबी ने ऋण, मुद्रा बाज़ार प्रतिभूतियों के मानदंड बदले

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वर्तमान बाज़ार परिदृश्य का प्रतिबिंबन करने के लिए निधि गृहों के संविभागों के लिए ऋण एवं मुद्रा बाज़ार के लिखतों के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रावधानों को आशोधित कर दिया है। 91 दिनों तक अथवा उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की अस्थिर दर वाली प्रतिभूतियों सहित मुद्रा और ऋण बाज़ार की समस्त प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अब उस भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा, जिस पर उनका उस विशिष्ट मूल्यांकन दिवस को क्रय-विक्रय किया जाता है। 91 दिन तक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों का उस विशिष्ट मूल्यांकन दिवस को क्रय-विक्रय न किए जाने पर उनका मूल्यांकन परिशोधन आधार पर किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने विदेशी वाणिज्यिक उधार मानदंडों को शिथिल किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉरपोरेटों (कम्पनियों) को आहरण द्वारा कमी और चुकौती कार्यक्रमों तथा मुद्राओं के अंतरण को भी आशोधित करने की अनुमति देते हुए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB) के दिशानिर्देशों को शिथिल कर दिया है। बैंक कम्पनियों को स्वत: अनुमोदित एवं अनुमोदित मार्गों के अधीन ऋण मुद्राएं परिवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते वे अन्य सभी शर्तं एवं निबन्धन पूरे करती हों। हालांकि, प्रस्तावित मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय होनी चाहिए। इसके अलावा, इस प्रकार के परिवर्तनों से ऋणों की औसत परिपक्वता अवधियां हरगिज नहीं प्रभावित होनी चाहिए। आहरण द्वारा कमी अथवा चुकौती कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना फार्म 83 में सांख्यिकी और सूचना प्रबन्धन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को शीघ्रतापूर्वक दी जानी चाहिए। हालांकि, विदेशी वाणिज्यिक उधार की मूल परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर चुकौती कें किसी भी पुनर्निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी ।

आधारभूत सुविधा बॉण्डों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक आधारभूत सुविधा बॉण्डों को अनिवार्य आरक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट नहीं दे सकता। बैंकों ने आधारभूत सुविधा बॉण्डों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात से मुक्त (उसके साथ ही सांविधिक चलनिधि

अनुपात से भी मुक्त) किए जाने की मांग की थी, क्योंकि अन्य जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात बढ़ाया जाने वाला है। उक्त छूट से उन्हें दीर्घावधिक प्रलेखों (papers) के मूल्य-निर्धारण में 100-150 आधार अंकों की कमी लाने तथा उन्हें निवेशकों की दृष्टि से और आकर्षक बनाने में सहायता प्राप्त हुई होती। हालांकि डॉ. चक्रवर्ती का कहना है, "वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध मुद्रा कुछ समय तक आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का निधीयन करने के लिए पर्याप्त है। यदि संपूर्ण रूप से नहीं, तो भी बैंक आधारभूत सुविधा के लिए उद्दिष्ट 20 लाख करोड़ रुपये के व्यय के 50-60 % का वित्तीयन करने में निश्चित रूप से समर्थ होंगे।" वर्तमान में आधारभूत सुविधा को कुल बकाया बैंक वित्त लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये है।

सेबी के अध्यक्ष ने विशेष सुविधा प्राप्त व्युत्पन्नियों के विरुद्ध चेतावनी दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री सी.बी. भावे ने नवोन्मेषी उत्पाद तैयार करने वाले बाज़ार के बिचौलियों की यह कहते हुए आलोचना की है कि वे (उत्पाद) और कुछ नहीं, अपितु अत्यधिक उत्तोलन (leverage) को छिपाने के तरीके हैं। श्री भावे ने यह टिप्पणी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कृत्रिम प्रतिभूतिकरण जैसे जटिल विन्यस्त उत्पादों और ऋण व्युत्पन्नियों के बारे में व्यक्त की गई चिंता के तुरंत बाद की, जिनकी अनुमति अब भारत की जोखिम प्रबन्धन क्षमताओं तथा विदेशों के अनुभवों का अध्ययन कर लिए जाने के बाद ही दी जाएगी। विशेष सुविधा प्राप्त व्युत्पन्नी उत्पादों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कई एक वित्तीय संस्थाओं का पतन हुआ, विश्वव्यापी ऋण संकट गहराया तथा आर्थिक मंदी की स्थिति निर्मित हुई। भारत में, कुछेक लोकप्रिय विन्यस्त उत्पादों में निफ्टी-सम्बद्ध डिबेंचरों, ऋण सम्बद्ध नोटों, दैनिक श्रेणी वाले उपचय नोटों, पुनरीक्षण विकल्पों तथा मैक्स ऑफ स्ट्रक्चरों का समावेश है। भारत में विन्यस्त उत्पादों के बाज़ार का आकार मोटे तौर पर 2 बिलियन डालर का है।

भारतीय रिज़र्व बैंक 3 वर्षीय वित्तीय समावेशन रूपरेखा के पक्ष में

अधिकतम वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से न्यूनतम जमा शेष की अपेक्षा के बिना अपवंचित लोगों को नो फ्रिल्स खातों की अनुमति देने के अलावा, ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके अलावा, पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की सीमा के सम्बन्ध में एक ऐसी 3 वर्षीय योजना की मांग की है, जिसे बैंक मार्च 2011 तक प्राप्त करेंगे। अब तक इस प्रकार की रूपरेखा की मांग केवल पूजी जुटाने की योजना जैसे वाणिज्यिक मामलों के सम्बन्ध में की जाती थी। वर्तमान में, भारतीय जनसंख्या के 60 % की पहुंच औपचारिक बैंकिंग सुविधा तक नहीं हो पाई है। स्थिर न्यायसंगत वृद्धि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 100 % वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। कोई समरूप मॉडल लागू करने के बजाय, भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि प्रत्येक बैंक उसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अनुसार स्वयं अपनी रणनीति तैयार करने हेतु स्वयं अपनी योजना तैयार करे। हालांकि, उसने यह सुझाव दिया है कि उक्त मॉडल में बैंकिंग बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराए जाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि जैसे तत्वों का समावेश होना चाहिए तथा उसमें नो फ्रिल्स खातों के साथ ही एक आंतरिक सुविधा के रूप में ओवरड्राफ्टों की व्यवस्था होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण दरें घटाईं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की दरों में अधोमुखी संशोधन किया है। अब बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर उच्चतम दर (पूर्ववर्ती लिबोर + 350 आधार अंक की तुलना में) लिबोर + 200 आधार अंक है। किए गए जेब-खर्च के रूप में वसूली प्रभार को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार का प्रभार, यथा - सेवा प्रभार और प्रबन्धन प्रभार नहीं वसूल किया जाएगा। ऐसे मामलों में, जहां आधार स्तर पर यूरो अंतरबैंक प्रस्तावित दर (यूरो लिबोर) का उपयोग किया गया है, इसी प्रकारके प्रभार लगाए जाएंगे। यह संशोधन केवल नये अग्रिमों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंकों के साथ की गई ऋण व्यवस्था पर उच्चतम ब्याज दर को छ माह का लिबोर / यूरो लिबोर / यूरिबोर + 150 आधार अंक से घटा कर छ माह का लिबोर / यूरो लिबोर / यूरिबोर + 100 आधार अंक कर दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेकों के लिए वर्धित सुरक्षा मानदंड निर्धारित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आप्टिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक चेकों के सीधे संसाधन में सहायता करने हेतु बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताएं और मानकीकृत क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। संशोधित न्यूनतम निर्धारणों अथवा चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) -2010 मानक के लिए रोलआउट समय सारणी बाद में घोषित की जाएगी। भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) परस्पर समन्वय करेंगे तथा इन विशेषताओं के सम्बन्ध में बैंकों को सूचित करेंगे। नई विशेषताओं में गुणवत्तापूर्ण कागज़ के उपयोग, द्योतकांक (watermark) और बैंक के प्रतीक (logos) का अदृश्य स्याही में मुद्रण, मानक आकार, कोलाहल-रहित पृष्ठभूमि तथा परा-बैंगनी छवियों (ultra violet images) के उपयोग का समावेश है। सुरक्षा विशेषताओं की सजातीयता के चेकों से सम्बन्धित धोखाधडियों के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करने की आशा है।

विशिष्ट घटनाएं

बैंक अधिकारी बनने के लिए गणित की ज़रूरत नहीं

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप अब गणित में कमजोर, यद्यपि अच्छी-खासी तार्किक एवं विवेचन योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति भी बैंक अधिकारी बन सकता है। 4000 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के भर्ती अभियान के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने यह तर्क देते हुए अंकीय योग्यता और मात्रात्मक रुझान वाले प्रश्नपत्र को छोड़ दिया था कि वर्तमान आर्थिक परिवेश में किसी अधिकारी को ठोस तर्कों के आधार पर त्वरित निर्णय लेने में अधिक सक्षम होना चाहिए।

विदेशी बैंक भारत के छोटे नगरों में पैठ बनाने को आतुर

भारत के छोटे नगर इस तथ्य को ले कर विदेशी बैंकों के प्रति उत्तेजित हैं कि सिटी और स्टैन्चार्ट जैसे बैंक कांचीपुरम, पानीपत और कोल्हापुर जैसे नगरों में अपनी पैठ बना रहे हैं। भारत में बैंकों को भारतीय रिज़र्व से लाइसेंस के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं है। विदेशी बैंक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अपने प्रतिस्थानियों की तुलना में अलाभकर स्थिति में हैं, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक एक वर्ष में 12 से अधिक विदेशी बैंकों को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

सेबी ने निवेशक शिक्षण को विद्यालयों तक पहुंचाया

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड संपूर्ण भारत के 26 विद्यालयों के कक्षा 8 और 9 के छात्रों के लिए निवेशक शिक्षा से नसीहत ले रहा है। तीन माह वाले इस स्वैच्छिक पाठ्यक्रम में छात्रों को मुद्रा के महत्व, उसका प्रबन्धन कैसे करें और बजट-निर्माण एवं बचत की संकल्पना की शिक्षा दी जाती है। सेबी यह महसूस करता है कि जीवन के शुरूआती दौर में उन्हें इस ओर आकर्षित करना ही एकमात्र वह तरीका है जिससे इक्विटी बाज़ार में निवेश करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (NISM) के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। श्री महेश व्यास, प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (CMIE) विचार व्यक्त करते हैं, "यह अत्यावश्यक है कि मूलभूत वित्तीय सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाया जाए; 25 और 75 वर्ष के बीच के आयु-वर्ग वाली जनसंख्या का केवल 40 % ही वित्तीय रूप से समावेशित है, अर्थात् बैंक खाता अथवा बीमा पॉलिसी या डिमैट खाता अथवा डेबिट / क्रेडिट कार्ड रखता है।"

समृद्ध ग्राहकों की तलाश में बैंक कस्बों की ओर

निजी बैंकिंग बाज़ार को बढ़ाने के अभियान में अब बैंक छोटे कस्बों के समृद्ध लोगों को लक्ष्यांकित कर रहे हैं। इन कस्बों में वृद्धि के अवसर काफी अधिक हैं, क्योंकि ये बाज़ार अभी तक अल्प-वेधित हैं। बैंक अधिकाधिक रूप से अपने निजी बैंकिंग कारबार - एक ऐसी वैयक्तीकृत बैंकिंग सेवा, जो खुदरा बैंकिंग के ऊपरी छोर को लक्ष्यांकित करती है, पर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं। इन सेवाओं में निवेश, धन-संपदा प्रबन्धन, संपदा प्रबन्धन, कर योजना तथा मज़दूर/ द्वारपाल (concierge) सेवाएं भी शामिल हैं। विशिष्ट रूप से निजी बैंकिंग के ग्राहक को 1.5 करोड़ रुपये से ले कर 5 करोड़ रुपये तक की श्रेणी में निवेश योग्य अधिशेष रखने की आवश्यकता होती है।

संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक थोक जमाराशियां जुटाने के प्रयास में

अगले कुछेक सप्ताहों में चलनिधि की स्थिति के कठिन होने की आशा के फलस्वरूप बैंकों ने बड़े जमा प्रमाणपत्र (CD) जारी करने के माध्यम से थोक जमाकर्ताओं को रिझाना आरंभ कर दिया है। आज की

तारीख तक केनरा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और कारपोरेशन बैंक सहित विविध बैंकों द्वारा 7000 करोड़ रुपये तक के जमा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। केवल इन्हीं बैंकों द्वारा ही जमा प्रमाण पत्र निर्गमों के माध्यम से 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई जा चुकी है। बताया जाता है कि संसाधन संग्रहण प्रयासों का एक हिस्सा आंशिक रूप से पुनर्निर्धारणीय परिपक्व हो रहे जमा प्रमाण पत्रों - पिछले वर्ष जारी अल्प और दीर्घ, दोनों ही अवधियों वाले का था। जमा प्रमाण पत्रों में निवेश की गई निधियां अधिकांशतया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम शोधन कम्पनियों सहित बड़े कॉरपोरेटों से थीं। यह कि चलनिधि की कठिन स्थिति आसन्न है, यह बात जमा प्रमाण पत्रों की दरों के स्थिर होने से ही स्पष्ट हो जाती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

टीजर दर : समायोज्य दर वाले बंधक (ARM) से सम्बन्धित एक प्रारंभिक दर। यह दर विशिष्ट रूप से प्रचलित बाज़ार दर से कम होगी तथा इसका उपयोग ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को इस बात के लिए प्रलोभित करने हेतु किया जाता है कि वे परंपरागत बंधकों की अपेक्षा समायोज्य दर वाले बंधक को चुने। टीजर दर केवल कुछेक माह तक ही प्रभावी रहेगी, जिस बिन्दु पर यह दर क्रमिक रूप से तब तक बढ़ेगी, जब तक कि वह उस संपूर्ण अभिसूचित दर पर नहीं पहुंच जाती, जो एक स्थिर मार्जिन दर जोड़ें वह अस्थिर दर सूचकांक, जिससे बंधक आबद्ध होता है (सामान्यतया लिबोर सूचकांक)।

शब्दावली

प्रावधान व्याप्ति अनुपात (PCR)

प्रावधान व्याप्ति अनुपात (PCR) सकल अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का अनुपात होता है और निधियों की उस सीमा का संकेत करता है जो कोई ऋणदाता ऋणगत हानियों को सुरक्षित रखने के लिए अलग रखता है। तकनीकी अथवा विवेकसम्मत बट्टे खाते डाली गई राशियां शाखाओं की बहियों में अनर्जक आस्तियों की रकमें होती हैं, किन्तु वे ऐसी रकमें होती हैं, जिन्हें प्रधान कार्यालय में अब भी बट्टे खाते डाला जाना है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) एक ऐसी राष्ट्रव्यापी प्रणाली है, जो व्यक्तियों को किसी भी बैंक शाखा से देश में किसी भी अन्य बैंक की शाखा में निधियों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से अंतरित करने की सुविधा प्रदान करती है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -12
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान (Institute) समाचार

10वां बैंक मानव संसाधन सम्मेलन आयोजित

संस्थान ने अपने 10वें बैंक मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन 15वीं फरवरी और 18वीं फरवरी, 2010 के बीच मारीशस में किया। उक्त सम्मेलन की विषय-वस्तु थी "प्रतिभा प्रबन्धन एवं समकालीन बैंकिंग की मानव संसाधन परंपराएं"। उद्घाटन भाषण सुश्री आयशा तिमोल, मुख्य कार्यपालक, मारीशस बैंकर संघ द्वारा दिया गया तथा मुख्य अभिभाषण प्रा. वाई. के. भूषण, सदस्य, शासी परिषद, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा दिया गया। उक्त सम्मेलन में लगभग 35 सहभागियों ने भाग लिया।

जेएआईआईबी के लिए ई-लर्निंग की शुरूआत

श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और अध्यक्ष, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स ने 20 फरवरी, 2010 को विश्व व्यापार केन्द्र में आयोजित एक अच्छी-खासी उपस्थिति वाले समारोह में जेएआईआईबी के सभी प्रश्नपत्रों के लिए ई-लर्निंग पैकेज़ की शुरूआत की। ई-लर्निंग की यह व्यवस्था जेएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है तथा यह पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं आदि जैसी अन्य अध्ययन सामग्रियों के अलावा है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सक्रिय प्रतिरूप कक्षाएं (LIVE Virtual classes)

इंस्टिट्यूट ने उन लोगों के लिए, जो आगामी जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरूप कक्षाओं (Live Interactive Virtual Education) की व्यवस्था की है। ये कक्षाएं 13 वीं मई 2010 से प्रारंभ होंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

संपर्क कक्षाएं

इंस्टिट्यूट आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी (मई / जून 2010) की परीक्षाओं के लिए चुनिंदा शहरों में संपर्क कक्षाओं का संचालन करेगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं की अद्यतन जानकारी

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे मई / जून 2010 में आयोजित होने वाली विविध परीक्षाओं के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

बाज़ार की खबरें

बाज़ार का आशुचित्र		(रकम मिलियन रुपयों में)		
संकेतक	05 फरवरी 2010	12 फरवरी 2010	19 फरवरी 2010	26 फरवरी 2010
मुद्रास्फीति (%)	7.31 % (जनवरी 2010)	7.31 % (जनवरी 2010)	8.56 % (जनवरी 2010)	8.56 % (जनवरी 2010)
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा प्रत्यावर्ती पुन: खरीद परिमाण	10,45,370	8,90,313	66,490	
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा पुन: खरीद परिमाण	0	0	0	0
औसत पुन: खरीद दरें (%)	2.68	2.96	3.09	2.52
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल (%	7.7462	7.9108	7.9454	7.9006
1-10 वर्ष का अंतर (आधार अंक)	296	312	313	321
6 माह का वायदा प्रीमियम (%)	2.82	2.80	2.44	2.77
6 माह का अमरीकी डालर लिबोर (%)	0.39	0.39	0.38	0.39

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के न्यूज़लेटर, फरवरी, 2010

भारित औसत मांग दरें

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

1.00
0.50
0

01/02/10 03/02/10 06/02/10 09/02/10 10/02/10 13/02/10 18/02/10 20/02/10
22/02/10 23/02/10 26/02/10

विनिमय दर
अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

46.40
46.35
46.30
46.25
46.20
46.15
46.10
46.05
46.00
45.95
45.90

पूर्वान्ह 11.30 बजे
अपरान्ह 5.30 बजे

01-02-10 15-02-10 26-02-10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केढ, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91 - 22 - 2218 51 47 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल :iibgen@bom5.vsnl.net.in
वेबसाइट : www.iibf.org.in

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2010